Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

NCCT CO-OP NEWS BULLETIN

Date: 02.02.2024

Sr No	Date	Publication	Edition	Page no.
1.	01-02-2024	Business Minutes	Madurai	
2.	01-02-2024	Agro Spectrum	Online	
3.	02-02-2024	Update Now	Indore	2
4.	02-02-2024	Pradesh Times	Bhopal	6
5.	02-02-2024	Dainik Kousar	Bhopal	7
6.	02-02-2024	Sandhya Praksh	Bhopal	2

Publication:	Business Minutes	Edition: Madurai	Print
Published Date:	February 01, 2024		

Amit Shah launches rural banks digitalisation scheme to ensure easy credit to farmers

NEW DELHI

Union Cooperation Minister Amit Shah has launched a Rs 120 crore initiative to computerize Agricultural and Rural Development Banks (ARDBs) in 13 states, a move aimed at streamlining loan processes and enhancing transparency for 1.2 crore farmers.

The project connects 1,851 ARDB units with NABARD through Common National Software, reducing transaction costs and providing real-time data access. This initiative aligns with the Digital India vision, extending the government's commitment to modernizing the cooperative system.

Shah emphasized the transformative impact on 1.2 crore farmers associated with ARDBs, reducing transaction costs and enabling real-time data access for improved scheme monitoring. The program is part of broader efforts under the Modi government's Digital India initiative, bringing cooperation to rural areas through digital means.

The comprehensive digitalization, costing approximately Rs 225 crore, covers ARDBs and Registrar of Cooperative Societies (RCSs). Shah highlighted the government's phased approach, starting with the computerization of Primary Agricultural Credit Societies (PACSs) and central registrar offices. The initiative culminates in the creation of a National Cooperative Database, providing accurate information at various levels and enhancing the cooperative sector's framework.

The Minister noted that the initiative enhances operations, efficiency, accountability, and transparency in ARDBs through the Common Accounting System (CAS) and Management Information System (MIS). The digitalization initiative signifies a major step toward bringing the entire cooperative sector into the digital realm, aligning with the government's vision for a more connected and transparent financial ecosystem for rural farmers.

Shah emphasized the government's commitment to reaching villages digitally under the Digital India initiative. The computerization of ARDBs and RCSs is expected to facilitate smoother loan distribution to farmers and contribute to the responsible and ethical use of technology in rural credit access. The initiative reflects the government's broader strategy to enhance the digital infrastructure within the cooperative sector, fostering transparency and efficiency in rural financial systems.

Publication:	Agro Spectrum	Edition:	Online
Published Date:	February 01, 2024		

Agri sector appreciates Union Budget 2024

https://agrospectrumindia.com/2024/02/01/agri-sector-appreciates-union-budget-2024.html

Mohan Kumar Mishra, Secretary, National Council of Cooperative Training (NCCT) said,
“This budget is people-centric and focuses on agriculture, rural development, and fisheries, with a strong emphasis on farmer cooperatives and value addition.
Many initiatives are continuations of previous budgets, aiming to strengthen the rural credit structure. Primary Agriculture Cooperative Credit Societies (PACS) are expected to emerge as multi-service centres for rural prosperity with financial support and credit availability.”

Publication:	Update Now, Pg 2	Edition: Indore	Online
Published Date:	February 02, 2024		

कृषि ग्रामीण विकास बैंक डिजिटलीकरण योजना शुरू

नई दिल्ली । केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 13 राज्यों में फैले कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) के लिए 120 करोड़ रुपये की कम्प्यूटरीकरण पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य उनके संचालन में पारदर्शिता बढ़ाना और लाखों किसानों को ऋण वितरण में सुविधा प्रदान करना है। यह पहल 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित एआरडीबी की 1,851 इकाइयों को कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ेगी। नई दिल्ली में परियोजना का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शाह ने कहा कि एआरडीबी शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण से उनसे जुड़े 1.2 करोड़ किसानों को काफी फायदा होगा. इसके अलावा, शाह ने कहा, कार्यक्रम लेनदेन लागत को कम करेगा, किसानों को ऋण वितरण की सुविधा प्रदान करेगा और योजनाओं की बेहतर निगरानी और मूल्यांकन के लिए वास्तविक समय डेटा तक पहुंच सक्षम करेगा। शाह ने कहा कि मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत सहयोग भी डिजिटल माध्यम से गांवों तक पहुंचना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के सहकारी समिति के रजिस्ट्रार कार्यालय एवं कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों के कम्प्यूटराइज़ेशन के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समिति से लेकर पूरी सहकारिता व्यवस्था को आधुनिक बनाने का काम किया है।

Publication:	Pradesh Times, Pg 6	Edition:Bhopal	Online
Published Date:	February 02, 2024		

अमित शाह ने किसानों को आसान ऋण सुनिश्चित करने के लिए डिजिटलीकरण योजना शुरू की

नई दिल्ली। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 13 राज्यों में फैले कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) के लिए 120 करोड़ रुपये की कम्प्यूटरीकरण पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य उनके संचालन में पारदर्शिता बढ़ाना और लाखों किसानों को ऋण वितरण में सुविधा प्रदान करना है।यह पहल 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित एआरडीबी की 1,851 इकाइयों को कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ेगी।नई दिल्ली में परियोजना का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शाह ने कहा कि एआरडीबी शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण से उनसे जुड़े 1.2 करोड़ किसानों को काफी फायदा होगा.इसके अलावा, शाह ने कहा, कार्यक्रम लेनदेन लागत को कम करेगा, किसानों को ऋण वितरण की सुविधा प्रदान करेगा और योजनाओं की बेहतर निगरानी और मूल्यांकन के लिए वास्तविक समय डेटा तक पहुंच सक्षम करेगा। शाह ने कहा कि मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत सहयोग भी डिजिटल माध्यम से गांवों तक पहुंचना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के सहकारी समिति के रजिस्ट्रार कार्यालय एवं कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों के कम्प्यूटराइज़ेशन के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) से लेकर पूरी सहकारिता व्यवस्था को आधुनिक बनाने का काम किया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि इन दोनों कामों में लगभग सवा दो सौ करोड़ रूपए की लागत आएगी, जिनमें से एआरडीबी (ARDB) पर 120 करोड़ रूपए और आरसीएस (RCS) पर 95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे । उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और मध्यम और दीर्घकालीन ऋण लेने वाले किसानों के लिए आज से एक सरल सुविधा की शुरूआत होगी।

Publication:	Dainik Kousar, Pg 7	Edition: Bhopal	Online
Published Date:	February 02, 2024		

अमित शाह ने किसानों को आसान ऋण सुनिश्चित करने के लिए कृषि ग्रामीण विकास बैंक डिजिटलीकरण योजना शुरू की

नई दिल्ली। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 13 राज्यों में फैले कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) के लिए 120 करोड़ रुपये की कम्प्यूटरीकरण पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य उनके संचालन में पारदर्शिता बढ़ाना और लाखों किसानों को ऋण वितरण में सुविधा प्रदान करना है। यह पहल 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित एआरडीबी की 1,851 इकाइयों को कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ेगी।

नई दिल्ली में परियोजना का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शाह ने कहा कि एआरडीबी शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण से उनसे जुड़े 1.2 करोड़ किसानों को काफी फायदा होगा. इसके अलावा, शाह ने कहा, कार्यक्रम लेनदेन लागत को कम करेगा, किसानों को ऋण वितरण की सुविधा प्रदान करेगा और योजनाओं की बेहतर निगरानी और मूल्यांकन के लिए वास्तविक समय डेटा तक पहुंच सक्षम करेगा। शाह ने कहा कि मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत सहयोग भी डिजिटल माध्यम से गांवों तक पहुंचना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के सहकारी समिति के रजिस्ट्रार कार्यालय एवं कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों के कम्प्यूटराइज़ेशन के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समिति से लेकर पूरी सहकारिता व्यवस्था को आधुनिक बनाने का काम किया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि इन दोनों कामों में लगभग सवा दो सौ करोड़ रूपए की लागत आएगी, जिनमें से एआरडीबी पर 120 करोड़ रूपए और आरसीएस पर 95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे । उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और मध्यम और दीर्घकालीन ऋण लेने वाले किसानों के लिए आज से एक सरल सुविधा की शुरूआत होगी। पिछले दो वर्षों में, मोदी सरकार ने सहकारी क्षेत्र के भीतर डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं। शाह ने कहा, मोदी सरकार ने सहकारी समितियों में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए चरणबद्ध तरीके से दूरगामी दूरगामी सोच के साथकाम किया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन के तुरंत बाद, पहले 65000 पैक्स, केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और फिर पैक्स के साथ साथ सभी ज़िला और राज्य सहकारी बैंकों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया गया और अब एआरडीबीएस और आरसीएस के कम्प्यूटरीकरण के साथ ही पूरा सहकारिता क्षेत्र आज डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि 65000 पैक्स के कम्प्यूटराइज़ेशन के लिए आधुनिक और लोगों के साथ संवाद करने योग्य सॉफ्टवेयर को नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया है और इसी के साथ ये सभी पैक्स इससे जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा, इसी प्रकार केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय के कम्प्यूटराइज़ेशन का काम भी पूरा हो चुका है, जिससे इस कार्यालय के सभी काम एक ही सॉफ्टवेयर से हो सकेंगे। शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के माध्यम से राज्यों, तहसील, ज़िला और ग्रामस्तर पर सहकारी समितियों की सही जानकारी सामने आ जाएगी जिससे सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इस रिक्तता को भरने के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। सहकारिता मंत्रालय की यह डिजिटलीकरण पहल सामान्य लेखा प्रणाली (सीएएस) और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से व्यावसायिक प्रक्रियाओं को मानकीकृत करके एआरडीबी के परिचालन, दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाने का काम करेगी।

Publication:	Sandhya Prakash, Pg 2	Edition: Bhopal	Online
Published Date:	February 02, 2024		

अमित शाह ने किसानों को आसान ऋण सुनिश्चित करने के लिए कृषि ग्रामीण विकास बैंक डिजिटलीकरण योजना शुरू की

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 13 राज्यों में फैले कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के लिए 120 करोड़ रुपये की कम्प्यूटरीकरण पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य उनके संचालन में पारदर्शिता बढ़ाना और लाखों किसानों को ऋण वितरण में सुविधा प्रदान करना है। यह पहल 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित एआरडीबी की 1,851 इकाइयों को कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ेगी।नई दिल्ली में परियोजना का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शाह ने कहा कि एआरडीबी शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण से उनसे जुड़े 1.2 करोड़ किसानों को काफी फायदा होगा.इसके अलावा, शाह ने कहा, कार्यक्रम लेनदेन लागत को कम करेगा, किसानों को ऋण वितरण की सुविधा प्रदान करेगा और योजनाओं की बेहतर निगरानी और मूल्यांकन के लिए वास्तविक समय डेटा तक पहुंच सक्षम करेगा।शाह ने कहा कि मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत सहयोग भी डिजिटल माध्यम से गांवों तक पहुंचना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के सहकारी समिति के रजिस्ट्रार कार्यालय एवं कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों के कम्प्यूटराइज़ेशन के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समिति से लेकर पूरी सहकारिता व्यवस्था को आधुनिक बनाने का काम किया है।

LOCATIONS OF NCCT INSTITUTES

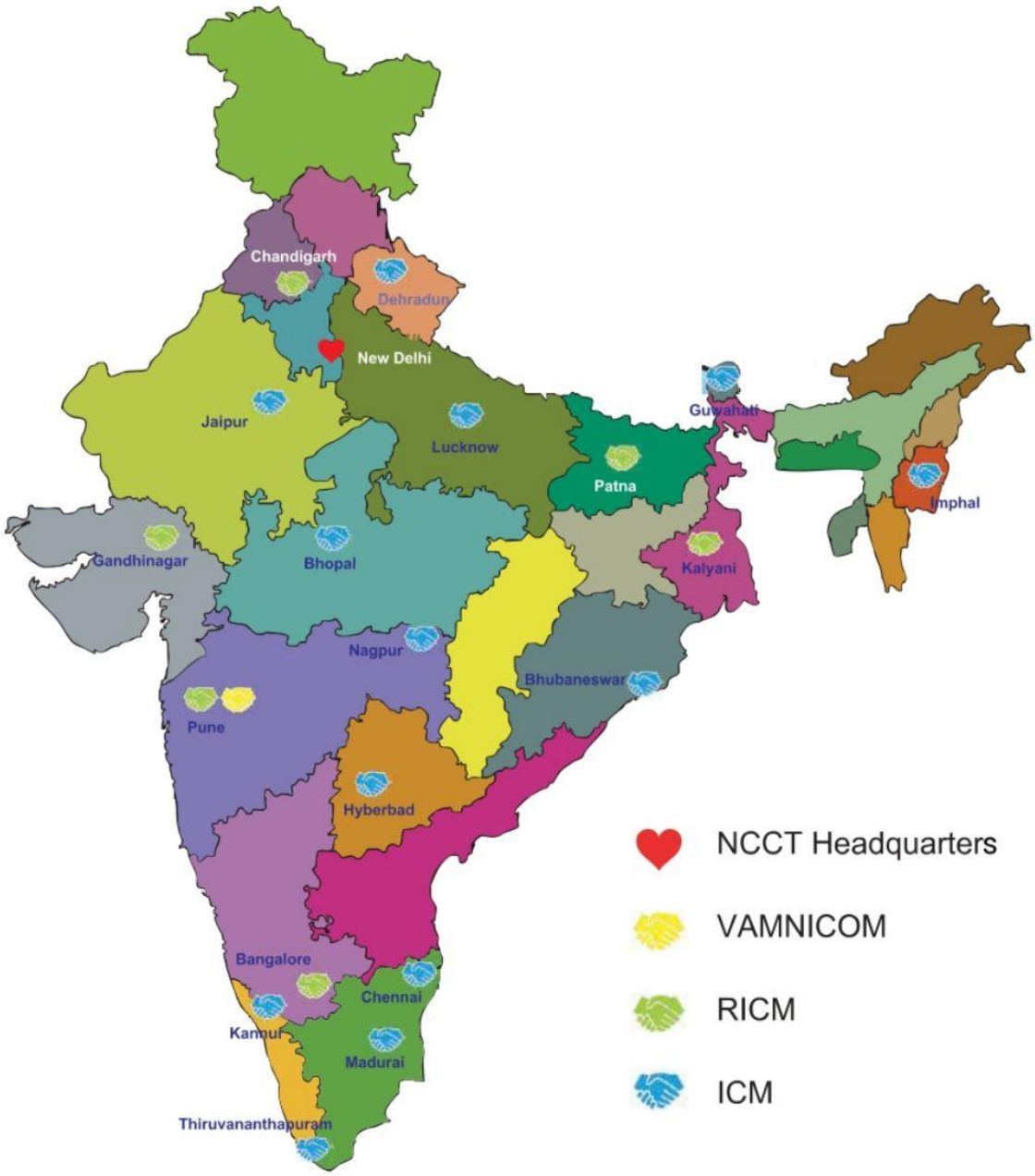

NATIONAL COUNCIL FOR COOPERATIVE TRAINING

(AN AUTONOMOUS SOCIETY PROMOTED BY MINISTRY OF COOPERATION, GOVERNMENT OF INDIA)

3, Siri Institutional Area (3rd Floor), August Kranti Marg, New Delhi-110016

011-41096510 secy-ncct@gov.in www.ncct.ac.in